Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 GISRRJ | Volume 4 | Issue 5 | ISSN : 2582-0095

भारत की आंतरिक सुरक्षा समस्याएं एवं चुनोतियाँ: भारतीय सुरक्षा बलों की भूमिका

डॉ. नर्वदेश्वर पाण्डेय
सह-आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन विभाग, का.सु.साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या
डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविधालय अयोध्या ।
विनोद कुमार
अनुसंधित्सु- रक्षा एवं स्त्रातजीय अध्ययन,का.सु .साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या

Article Info
Volume 4 Issue 5
Page Number: 24-29

Publication Issue :
September-October-2021

Article History
Accepted : 01 Sep 2021
Published : 05 Sep 2021

शोध सारांश- किसी भी देश के नागरिकों में जब असुरक्षा की भावना का भाव होता है, तब उस देश का विकास रुक जाता है, क्योंकि वहाँ का प्रशासन लोगों के साथ न होकर आंतरिक चुनोतियो से लड़ रहा होता है। भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के अधीन तीनों सेनाओं की होती है। आंतरिक सुरक्षा को बनाये रखने के लिए अलग अलग सुरक्षा बल, सुरक्षा एजंसियां और राज्य पुलिस बलों की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन आज का बदलता बाह्य परिवेश हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है, इसलिये जरूरी है, कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक नीतियाँ बनाई जाए इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासन सेवा के रूप में अलग से केंद्रीय सेवा बनाई जाए ताकि आंतरिक खतरों से आसानी से निपटा जा सकें।

शब्दकोश: सुरक्षा, आंतरिक–सुरक्षा, आंतरिक–खतरे, बाह्य–खतरे, सम्प्रभुता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातिवाद, नक्सलवाद, विप्लवाद, आतंकवाद आदि।

परिचय- भारत में संघीय ढांचा है, जिसको दो भागों में बॉटा गया है। केंद्र और राज्य, दोनों के पास अलग– अलग शक्तियाँ है। केंद्र के सभी विषय भारतीय संघ की 7वी सूची में और कानून के विषय को राज्य सूची में रखा गया है। इस प्रकार देश को संचालित करने के लिये दो प्रकार के मुद्दों से समझा जा सकता है। जिसमें केंद्र को पूरे देश की आंतरिक जिम्मेवारी दी गई है, जिसे हम आंतरिक सुरक्षा कहते है, जबकि राज्य को कानून व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेवारी दी गई है।

आंतरिक सुरक्षा का अर्थ– एक देश द्वारा 'अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा' को आंतरिक सुरक्षा कहा जाता है, जिसमें शामिल है।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

1.राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा
2.देश में आंतरिक शांति को बनाए रखना
3.कानून का राज स्थापित करना और
4.साम्प्रदायिक सौहार्द बना कर रखना

आंतरिक सुरक्षा में उन्ही घटनाओं को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्र की सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की वह क्षमता है। जो अपने आंतरिक मूल्यों को बचाने का प्रयास करता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के अभाव में, कोई भी राष्ट्र अपनी अखंडता को बनाये रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से विकास नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र को खतरा दो प्रकार से हो सकता है, एक बाह्य खतरा और दूसरा आंतरिक खतरा लेकिन जब खतरा बाह्य होता है, तो ये राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में आता है। जबकि आंतरिक खतरा राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों क्षेत्रों से सम्बंधित होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का वर्णन करते हुए आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है ' कि राष्ट्र को चार प्रकार के खतरों से सामना करना पड़ता है।

1.आंतरिक सुरक्षा
2.बाह्य सुरक्षा
3.बाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक और
4.आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी। आज भारत आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी सुरक्षा चुनोतियों का सामना कर रहा है, इसका ज्वलन्त उदाहरण रोज–रोज भारत के खिलाफ बनती नई–नई टूल–किट है, जिनकी मद्त से भारत को डिस्टर्ब किया जाता है आज आंतरिक सुरक्षा पारंपरिक युद्ध की बजाए प्रॉक्सी युद्ध के रूप में हमारे लिए एक बड़ी चुनोती बन गई है।

आंतरिक सुरक्षा के लिये जिमेदार कारक

विरासत में मिले कारक – विरासत में मिले कारकों में सबसे पहले आता है, भारत की भौगोलिक स्थिति जो उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याक्वारी तक लगभग 3200 किलोमीटर में है, इसी प्रकार पूर्व में अरुणाचल से लेकर पश्चिम के कच्छ तक लगभग 2900 किलोमीटर में फैली है। 11 बड़े बन्दरगाहों में 95 प्रतिशत व्यापार इन्हीं पर बने समुद्री मार्गों से होता है जो आंतरिक सुरक्षा के लिये बहुत बड़ी चुनोती हैं।

दूसरा कारक है पड़ोसी देश पड़ोसी देश भी आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव डालते है। जैसे पाकिस्तान जब से बना है। हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा ही रहा है। प्रत्यक्ष रूप से चार बार युद्ध हार चुका है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है । चीन भी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और साथ ही चीनी मद्त पाकर नेपाल की भूमिका भी पहले जैसी नहीं रही इसके अलावा बांग्लादेश के शरणार्थियों की समस्या,श्रीलंका मालदीप सभी पड़ोसी देश भारत के लिए नई–नई चुनोतिया खड़ी करते है।

तीसरा कारक गरीबी है, जो हमे विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है, कि इसमें सुधार नही हुआ है लेकिन आज भी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 26 प्रतिशत लोगों की मासिक आय 816 रु बताती है चौथा कारक है बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा युवा रहते है और विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी यही पर है।

प्रशासनिक विफलता:– ऐसा नहीं है केवल विरासत में मीले कारणों से ही हमारी आंतरिक सुरक्षा कमजोर हुई है, बल्कि प्रशासन में बैठे नीति निर्माताओं और उन नीतियों को धरातल पर लागू न कर पाने वाले प्रशासन अधिकारियों की विफलताओं के कारण भी आंतरिक सुरक्षा कमजोर हुई हैं जिनमे मुखयत: शामिल है:–

1.असमानता और असन्तुलित विकास ।

2.अमीर गरीब के बीच अंतर ।

3.सुशासन की कमी ।

4. लाल फीता शाही का दबाव ।

दलगत राजनीति- यदि हम ये कहे कि प्रशासन विफलता का मुख्य कारण दलगत राजनीति रही है तो गलत नहीं होगा वैसे तो दलगत राजनीति लोकतंत्र में अच्छी समझी जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाया बल्कि इसने भारतीय लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा को कमजोर ही किया जिसको हम इस रूप में देख सकते है ।

1.साम्प्रदायिकता में बृद्धि ।

2.जातिवाद में बढ़ोतरी ।

3.क्षेत्रवाद पर राजनीति ।

4.भाषावाद की लड़ाई ।

शासकीय अक्षमता:- शासकीय अक्षमता भी आंतरिक सुरक्षा के लिये एक अभिशाप है, क्योंकि इसकी विफलता लोगों के अंदर विश्वास की कमी को बढ़ाता है, जिसके कारण लोगों का न्याय प्रणाली से मोहभंग होता है, जिसका मुख्य कारण है:-

1.धीमी न्याय प्रणाली

2.भ्रष्टाचार

3.पुलिस और नेताओं की सांठगांठ

आंतरिक सुरक्षा के लिये उत्पन्न चुनोतियाँ- भारत की भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी देशों का व्यवहार , स्थलीय, वायु, और समुद्री सीमाओं का विस्तार तथा इतिहास से मिले सबक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी चुनोती उत्पन्न करते है, जिसमें शामिल है।

1.नक्सलवाद - नक्सलवाद की उतपति पश्चिम बंगाल के गाँव नक्सलवाड़ी से हुई थी जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और आज ये पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनोती बना हुआ है. यह दो प्रकार का होता है एक माओवाद और दूसरा वामपंथी उग्रवाद ।

2.धार्मिक कटरता- भारत में हर साल धार्मिक दंगे होते है. जो बहुलतावादी संस्क्रति को छीन भिन कर देते है। जिसका फायदा पड़ोस में बैठा दुश्मन आसानी से उठा सकता है।

3.आतंकवाद-किसी भी प्रकार का आतंकवाद चाहे वो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय हो देश में केवल भय का माहौल पैदा करता है।

4.विप्लवाद- जब किसी क्षेत्र के लोग अपने ही संविधान को मानने से मना कर दे तब अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है । जैसे पूर्वी राज्यों में मणिपुर नागालेंड पंजाब में खालिस्तानी ।

5.सीमा प्रबन्धन- सीमा प्रबन्धन भी आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बहुत बड़ी चुनोती है। जो समय समय पर सामने आती रहती है।

संगठित अपराध- आर्थिक लाभो के लिए व्यक्तियों का संगठित दल जिसमें वो अपरहण, तस्करी, डकैती, अवैध वसूली आदि कार्यों में लगे रहते है।

6.आर्थिक अपराध- इसमें वाइट मनी/ब्लैक मनी में लगे लोग, मनी लॉड्रिंग, हवाला कारोबारी गैर-पारंपरिक अपराधो में शामिल लोग आंतरिक सुरक्षा को चुनोती है।

7.साइबर सुरक्षा- साइबर सुरक्षा भी भारत में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ी चुनोती है।

सुरक्षा बलों की भूमिका- आंतरिक सुरक्षा की जिमेवारी ग्रह मंत्रालय की होती है जिसमें सुरक्षा बलों की भूमिका विशेष होती है, इसके अलावा बहुत सी गुप्तचर एजेंसिया, जांच एजंसियां और विधि द्वारा बनाये गए कानूनों की भूमिका का बड़ा महत्व है।

सुरक्षा बल - कुछ सुरक्षा बल सीमा प्रबन्धन का काम करते है, जिसमें मुख्यत: शामिल है–

1.सीमा सुरक्षा बल- BSF यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। इसको 1 दिसम्बर 1965 में खड़ा किया गया था। इसका काम शांति काल के दौरान देश के बार्डर की सुरक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय अपराध को रोकना है। भारत सरकार BSF की जिमेवारी का क्षेत्र खतरों के अनुसार राज्यों में कम ज्यादा कर सकती है। जैसे अभी सरकार ने पंजाब और पश्चिम बंगाल में BSF का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया और मणिपुर,त्रिपुरा,मिजोरम,और नागालेंड का कम कर दिया। BSF की स्थापना 25 बटालियनों के साथ हुई थी लेकिन अब इसमें 188 बटालियन है और ये सभी 6385 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जरनल श्री एस एस देसवाल आईपीएस हैं।

2.भारत तिबत सीमा पुलिस-ITBP का गठन चीनी आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में हुआ था इसका कंट्रोल पहले IB के पास था । लेकिन बाद में 1975 में इसके काम में बदलाव करते हुए सीमा पार घुसपैठ को रोकने के लिये कर दिया इस बल का आदर्श वाक्य शौर्य-दृढ़ता-कर्मनिष्ठ है, ये जवान मान-सरोवर यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान भी करते है। इस बल की 4 विशेष बटालियन के साथ कुल 29 बटालियन है। ये बटालियन सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपलेख दर्रा और भारत नेपाल त्रिसंगम तक लगभग 2115 किलोमीटर में फैली भारतीय सीमा की सुरक्षा करता है। इसमें लगभग 90 हजार सैनिक है। और डायरेक्टर जरनल श्री संजय अरोरा आईपीएस है।

3.सशत्र सेना बल-SSB पर भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिमेवारी है जो लगभग 1751 किलोमीटर लम्बी है, इसका गठन 1963 में किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य सीमाव्रती लोगों में विश्वास और देश भगति की भावना पैदा करता है। SSB के डायरेक्टर जरनल श्री कुमार राजेश चंद्र आईपीएस है।

4.केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल- CRPF भारत का सबसे बड़ा सशत्र बल है। इस बल की स्थापना 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे पहले क्राउन रिप्रजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था । इसके ऑफिसर ट्रेनिंग कोयम्बटूर, नांदेड़,नीमच,और माउंटआबू अकेडमी में होती है। RPF रेपिड एक्शन फ़ोर्स भी इसी का एक भाग है, जिसकी स्थापना 1992 में दंगो को काबू करने के लिये की गई थी। इस बल में लगभग 230 बटालियन है। इस बल को भारत के किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भेजा जा सकता है। वर्तमान समय मे इसके डायरेक्टर जरनल श्री कुलदीप सिंह आईपीएस है।

5.केंद्रीय ओधोगिक सुरक्षा बल-CISF इस सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी इसका मुख्य कार्य सरकारी उपक्रमों ,मेट्रो, परमाणु संस्थान और VIP सुरक्षा करना है। इसके ऑफिसर ट्रेनिंग अकैडमी हमीपपेट हैदराबाद में है। इस समय लगभग 1.5लाख कर्मचारी इस बल में कार्यरत है और इनके डायरेक्टर जरनल श्री शील वर्धन सिंह आईपीएस है।

6.राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड–NSG इसका मुख्य काम देश में आतंकवादियों के खिलाफ कारवाई करना है। इसकी स्थापना 1986 में कई गई थीं। इस बल के 2 ग्रुप है, एक SAG यानी स्पेशल ऐक्शन ग्रुप जिसमें सैन्य कर्मचारी होते है और दूसरा ग्रुप SRG जिसमें स्टेट पुलिस के कर्मचारी होते है। इन्हें ब्लैक बेल्ट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ट्रेनिंग हरियाणा के मानेसर में होती है, इनका नेतृत्व IPS महानिदेशक करता है। इस बल में 14500 कर्मी है और इसके डायरेक्टर जरनल श्री एम ए गाणपत्य 1986 बैच के आईपीएस है।

7.असम राइफल्स– AR असम राइफल्स को पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है और प्यार से लोग इसे पूर्वोत्तर के प्रहरी नाम से पुकारते है। इस बल की 48 बटालियन है, जो पूर्वोत्तर भारत–म्यंमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है। इसकी स्थापना 1835 में क्रेशर लेवी के नाम से की गई थी। बाद में इसका नाम असम फ्रंटियर पुलिस,1891में असम मिल्ट्री पुलिस और 1913 में ईस्टर्न बंगाल कर दिया, लेकिन फिर से 1917 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स रख दिया जो आज भी है, दूसरे विश्व युद्ध में असम राइफल्स ने बर्मा में मुख्य भूमिका निभाई थी। आज इस सुरक्षा बल में लगभग 66411 सैनिक सक्रिय है इस समय डायरेक्टर जरनल ऑफ असम राइफल्स(DGAR) जरनल प्रदीप चन्द्रन नायर है। इन सभी बलो के पास अपने स्वयं के अधिकारियों का कैडर है, लेकिन वे सभी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के नेतृत्व में काम करते है। और देश में आने वाली किसी भी कैसी भी चुनोती का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं।

गुप्तचर एजंसियां– सुरक्षा बलों के अलावा गुप्तचर एजंसियां भी अपना काम करती है और आंतरिक खतरा होने से पहले ही उसे रोक देती है, जिनमे मुखयत:

1.रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग)

2.आई बी (इंटेलिजेंस ब्यूरो)

3.एन आई ए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी)

4.एन टी आर ओ (नेशनल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन)

5.एन सी बी (नरोकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो)

डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी

एयर, नेवी, और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी आदि है।

जांच एजेन्सियाँ

1.केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI

2.केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC

3.प्रवर्तन निदेशालय ED

निष्कर्ष– आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार भी प्रयासरत है। सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरण दिए जा रहे है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेन्सी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति बनाना ये सभी कार्य अपने–अपने स्तर पर चल रहे हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है, आज भी पाकिस्तान समर्थित लोग भारत के अंदर पाकिस्तान झण्डों के साथ सुरक्षा बलों को चेलेंज करते है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देश की राजधानी में दिया जाता है और बाद में ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर टी–वी पर लाइव डिबेट में आते है। सरकार इनके विरुद्ध कारवाही करने की बजाए मूकदर्शक और डिफेंसिव हो जाती है। भारत सरकार को ऐसी चुनोतियों का दृढ़ता पूर्वक सामना करना होगा और रोज–रोज

हो रहे नकली आंदोलनों, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से कंट्रोल किया जाता है, इस पर सकती से कारवाही करनी होगी। देश में पनप रही आर्थिक समस्याओं को युद्ध स्तर पर दूर करना होगा। जो लोग मुख्य विचारधारा से दूर चले गए है, उन्हें वापिस मिलाने के लिए प्रेरित करना होगा और यदि जरूरत पड़ती है, तो उनके विरुद्ध सख्ती के साथ पेश आना होगा । वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक नीतियां बनानी होगी जिस प्रकार यूरोप के देश प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों के अनुसार अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धान्तों में बदलाव करते रहते है,हमे भी वैसा ही करना होगा, लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण हम आज तक न तो कश्मीर को लेकर और न ही उतर पूर्वी भारत को लेकर कोई दीर्घकालिक नीति है, बना पाये है। माओवादी विद्रोह से निपटने के लिये भी कोई रणनीति नही है। सर्वोच्च न्यालय के आदेश 2006 में पुलिस सुधार को लेकर आज तक पुलिस विधयक को अंतिम रूप नही दे पाए जिसके कारण देश के खिलाफ बोलने पर, देश को गाली देने पर पुलिस देश द्रोह की धारा लगाने में संकोच करती है और यदि लगा भी देती है तो व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अदालत उसे छोड़ देती है, जिसके कारण आंतरिक सुरक्षा को खतरा और बढ़ जाता है इसलिये भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रसाशन सेवा के रूप में एक अलग से केंद्रीय सेवा बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है सरकार लगातार प्रयासरत है ताजा घटनाक्रम में एफ.सी.आर.य (foreign contribution Regulations Act) पर पाबन्दी लगाना इसका संकेत है। अब कोई भी NGO सरकार को बताए बिना विदेश से फंडिंग लेकर गैर कानूनी गतिविधियों पर आसानी से खर्च नहीं कर सकता इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री का वो ट्वीट विश्वास पैदा करता है, जिसमें रक्षा मंत्री कहते है'कि अब भारत ने अपना आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लिया है, कि एक और 26/11 को हिंदुस्तान की धरती पर अंजाम देना अब लगभग नामुमकिन है' इस प्रकार यह कहा जा सकता है। अब भारत की आंतरिक सुरक्षा को भेद पाना इतना आसान नहीं हैं, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ घटक है, जिन पर सरकार को और कार्य करने की जरूरत है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. नेशनल सिक्योरटी(ज एम श्रीवास्तव, हर्ष कुमार) ए एस आर पब्लिकेशन, लखनऊ यूपी- 2018
2. ऱक्षा एवं स्ट्रेटजिक अध्ययन(अशोक कुमार) प्रकाश बुक डिपो,नई दिल्ली-2018
3. भारत की आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनोतियाँ (अशोक कुमार आईपीएस) मकग्रो हिल एजुकेशन इंडिया, नोएडा यूपी-2019
4. भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं प्रबन्धन (अमन कुमार आईपीएस) प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटिड, नई दिल्ली- 2018
5. इंटरनल सिक्योरिटी फ़ॉर सिविल सर्विसेज (पवनीत) मकग्रो हिल एजुकेशन इंडिया,नोएडा यूपी- 2021
6. आंतरिक सुरक्षा(मोहन) 2019 EG प्रकासन E-Book
7. भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनोतियाँ और समाधान (विवेक ओझा) अक्षर पब्लिकेशन गुजरात- 2020
8. सुरक्षा अध्ययन (प्रो.डॉ.एल के मिश्र) आकृति प्रकासन दिल्ली- 2018
9. अखबार और पत्रिकाएं
10. एनालिसिस, IDSA, नई दिल्ली
11. वर्ल्ड फोकस जर्नलस नई दिल्ली
12. डिफेंस मोनिटर हिन्दी दिल्ली
13. सैनिक समाचार नई दिल्ली
14. प्रतियोगिता दर्पण आगरा

15. समसामयिक अवलोक
16. दैनिक ट्रिब्यून नई दिल्ली
17. टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली
18. इंटरनेट (E-Resource)